



12 July, 2024

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा

संदर्भ: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने डिजिटल बाजारों के लिए एक समर्पित प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए हाल ही में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) पर एक समिति का गठन किया।

➤ CDCL की स्थापना और डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का परिचय:

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने डिजिटल बाजारों में विशिष्ट प्रतिस्पर्धा नियमों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए फरवरी 2023 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) पर समिति का गठन किया।
- CDCL ने मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को एक पूर्व-नियामक ढांचे के साथ बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की शुरुआत की सिफारिश की।
- इस ढांचे का उद्देश्य यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम से प्रेरित होकर डिजिटल बाजारों में संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों को होने से पहले ही सक्रिय रूप से संबोधित करना है।

➤ पूर्व-नियामक ढांचे को समझना:

- वर्तमान प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, प्रस्तावित पूर्व-नियामक ढांचा डिजिटल बाजारों में हानिकारक प्रथाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसे डिजिटल व्यवसायों के तेज विकास और अनूठी विशेषताओं, जैसे नेटवर्क प्रभाव और पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका लक्ष्य डिजिटल एकाधिकार के गठन को रोकने के लिए समय रहते हस्तक्षेप करना और बाजार प्रभुत्व के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।

➤ डिजिटल बाजार की विशेषताएं और चुनौतियां:

- डिजिटल बाजारों को पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ मिलता है, जिससे कुछ बड़ी फर्मों द्वारा तेजी से विस्तार और प्रभुत्व की अनुमति मिलती है।
- नेटवर्क प्रभाव डिजिटल सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ाता है क्योंकि अधिक उपयोगकर्ता इसमें शामिल होते हैं, जिससे संभावित रूप से बाजार में एकाग्रता और कम प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- डिजिटल एकाधिकार के उद्भव को रोकने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए वर्तमान नियामक ढांचे की चपलता के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

➤ मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- विधेयक प्रमुख डिजिटल प्रतिस्पर्धियों की पहचान करने के लिए "महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत" और "महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता आधार" जैसे मानदंडों का प्रस्ताव करता है।
- यह निष्पक्ष प्रथाओं, गैर-भेदभाव और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों" (SSDE) के लिए दायित्वों का परिचय देता है।

- निषिद्ध प्रथाओं में स्व-वरीयता, एंटी-स्टीयरिंग प्रथाएं और उपभोक्ता डेटा का अनधिकृत उपयोग शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

➤ समर्थन और आलोचना:

- कुछ भारतीय स्टार्टअप इस विधेयक का समर्थन बड़ी तकनीकी फर्मों द्वारा बाजार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के उपाय के रूप में करते हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि पूर्व-पूर्व दृष्टिकोण भारत के बाजार की गतिशीलता के लिए उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि यूरोपीय संघ में है, जिससे संभावित रूप से नवाचार और स्टार्टअप विकास बाधित हो सकता है।
- छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSME) पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, विशेष रूप से बंडलिंग जैसी व्यावसायिक रणनीतियों पर प्रतिबंधों के बारे में, जिसका उपयोग वे प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए करते हैं।
- स्थानीय स्टार्टअप के विकास का समर्थन करने के लिए मानदंडों को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया गया है कि विनियामक उपाय अनजाने में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे खिलाड़ियों को नुकसान न पहुंचाएँ।

विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार, इस सदी में दुनिया की आबादी के चरम पर पहुंचने की 80% संभावना है, जबकि एक दशक पहले यह 30% थी।

➤ वैश्विक जनसंख्या रुझान:

- 2080 के दशक के मध्य तक दुनिया की आबादी लगभग 10.3 बिलियन के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद सदी के अंत तक धीरे-धीरे घटकर 10.2 बिलियन हो जाएगी।
- यह अनुमान पहले के अनुमानों से काफी कम है, जो दुनिया भर में प्रजनन दर में पर्याप्त गिरावट को दर्शाता है।

➤ जनसांख्यिकीय बदलाव और चुनौतियां:

- प्रत्येक वर्ष चार में से एक व्यक्ति ऐसे देशों में रहता है जहाँ आबादी पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है, और 2025 और 2054 के बीच 48 अन्य देशों में आबादी के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत के सदी भर में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का अनुमान है, जो अद्वितीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।

➤ जनसंख्या गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक:

- वैश्विक स्तर पर घटती प्रजनन दर, बढ़ती शिक्षा और गर्भनिरोधकों तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होकर, वैश्विक जनसंख्या में अपेक्षा से पहले चरम पर पहुंच रही है।

Face to Face Centres





12 July, 2024

- कई विकासशील देशों में आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा में सुधार जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को तेज कर रहे हैं।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक निहितार्थ:**
 - स्वास्थ्य सेवा में सुधार के बावजूद, उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में उच्च बाल मृत्यु दर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।
 - दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती उम्र की आबादी स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करती है, जिसके लिए व्यापक दीर्घकालिक देखभाल समाधानों की आवश्यकता होती है।
- **आर्थिक और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ:**
 - युवा आबादी वाले देशों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
 - लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली नीतियाँ जनसंख्या गतिशीलता को स्थायी रूप से प्रबंधित करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य:**
 - वर्तमान में लगभग 1.39 बिलियन की आबादी वाला भारत, 21वीं सदी में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा।
 - प्रतिस्थापन प्रजनन दर को पार करने के बावजूद, जनसांख्यिकीय गति के कारण भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के मध्य तक बढ़ती रहेगी।
 - अनुमान है कि 2050 के दशक तक भारत की 60% से अधिक आबादी कामकाजी आयु वर्ग में होगी, जो जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर प्रस्तुत करती है।
 - भारत को 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर 43 जन्मों की उच्च किशोर प्रजनन दर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो पिछले सर्वेक्षण अवधि (NFHS-4, 2015-16) में 51 से कम है।
 - भारत में लगभग पाँच में से एक लड़की अभी भी 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित है, जो समय से पहले गर्भधारण और उच्च जोखिम वाले जन्मों में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
 - शिक्षा में निवेश, विवाह में देरी, और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों और कार्यबल भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

हीट डोम

संदर्भ: पिछले सप्ताह से पूरे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में भीषण गर्मी की लहर चल रही है, जिससे लगभग 75 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, तथा तापमान के रिकॉर्ड टूट गए हैं।

- **परिभाषा:** हीट डोम तब होता है जब उच्च वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र अपने नीचे गर्म हवा को फंसा लेता है, जिससे लंबे समय तक गर्म मौसम बना रहता है।
- **अवधि और तीव्रता:** ये मौसमी घटनाएँ कई दिनों से लेकर हफ्तों तक बनी रह सकती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है क्योंकि फंसी हुई गर्म हवा लगातार गर्म होती रहती है।

- **तंत्र:** उच्च दबाव प्रणाली के कारण हवा जमीन के पास नीचे गिरती है और संकुचित होती है, जिससे और अधिक गर्मी होती है तथा बादल बनने और वर्षा की संभावना कम हो जाती है।
- **जेट स्ट्रीम इंटरैक्शन:** हीट डोम का निर्माण और गति जेट स्ट्रीम के व्यवहार से प्रभावित होती है, जो घुमावदार या धीमी होने पर स्थिर उच्च दबाव प्रणाली का कारण बन सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव:** वैज्ञानिकों का सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदलकर और वैश्विक स्तर पर समग्र तापमान को बढ़ाकर हीट डोम घटनाओं को बढ़ा सकता है।

➤ हीट डोम गठन के कारण:

- **महासागर तापमान प्रवणता:** महासागर की सतह के तापमान में तेज बदलाव संवहन प्रक्रियाएँ शुरू कर सकते हैं, जहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है और महासागर के ऊपर पूर्व की ओर बढ़ती है।
- **वायुमंडलीय दबाव की गतिशीलता:** किसी क्षेत्र में उतरने वाले उच्च दबाव वाले सिस्टम गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे सतह का तापमान बढ़ता है और बादल निर्माण और हवा दब जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन की भूमिका:** जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक तापमान में वृद्धि अधिक लगातार, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरों में योगदान करती है, जिससे हीट डोम की स्थिति और खराब हो जाती है।
- **मानवीय प्रभाव:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसी जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली गतिविधियाँ, मौसम के पैटर्न और मानव स्वास्थ्य पर हीट डोम के बिगड़ते प्रभावों में शामिल हैं।

➤ जेट स्ट्रीम की भूमिका:

- हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से प्रभावित होता है, जो एक उच्च-ऊँचाई वाली वायु धारा है जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौसम प्रणालियों को चलाती है।
- जब जेट स्ट्रीम का तरंग पैटर्न लंबा हो जाता है और धीमा हो जाता है, तो यह उच्च दबाव प्रणाली को स्थिर कर सकता है, जिससे हीट डोम का निर्माण होता है।

➤ हीट डोम पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन ने हीट डोम घटनाओं को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वे बड़ी और अधिक तीव्र हो गई हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि हाल ही में जून 2021 के कनाडाई हीट डोम जैसी अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव होतीं।
- शोध से संकेत मिलता है कि हीट डोम की तीव्रता वैश्विक वार्मिंग की समग्र दर से अधिक तेजी से बढ़ रही है, जो उनकी गंभीरता और आवृत्ति को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका को रेखांकित करता है।

Face to Face Centres





12 July, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

बिम्स्टेक



हाल ही में, भारत ने म्यांमार में चल रहे संकट के बीच बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मेजबानी की।

बिम्स्टेक के बारे में:

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे सात सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- इसे शुरू में बैंकोंक घोषणा के परिणामस्वरूप 6 जून, 1997 को चार सदस्य देशों (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड) के साथ गठित किया गया था।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यटन और कृषि सहित कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और कार्य समूहों के माध्यम से संचालित होता है।
- यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाता है।
- बिम्स्टेक के सिद्धांतों में संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ शामिल हैं। इसका स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।

रोबोट टैक्स



हाल ही में, RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने AI तकनीकों के कारण विस्थापित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निधि देने के लिए 'रोबोट टैक्स' का प्रस्ताव रखा।

रोबोट टैक्स के बारे में:

- रोबोट टैक्स उन कंपनियों पर प्रस्तावित कर है जो स्वचालन तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स को अपनाती हैं, जिसका उद्देश्य संभावित सामाजिक लागतों, जैसे कि नौकरी के विस्थापन को ऑफसेट करना है।
- यह कर रोजगार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनाने के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तावित है।
- इसका उद्देश्य AI और स्वचालन का उपयोग करने वाली कंपनियों पर कर लगाना है जिससे उन कर्मचारियों को सब्सिडी दी जा सके जो तकनीकी प्रगति के कारण नौकरी खो सकते हैं।
- इस प्रस्ताव में उन उद्योगों के लिए कर प्रोत्साहन भी शामिल हैं जो उच्च रोजगार-उत्पादन अनुपात को प्राथमिकता देते हैं।

नाटो



हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का मुकाबला करने के लिए नाटो सदस्यों से अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने का आग्रह किया, जिसमें चीन, ईरान और उत्तर कोरिया द्वारा समर्थित रूस के बढ़ते रक्षा उत्पादन का हवाला दिया गया।

नाटो के बारे में:

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।
- यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 देशों से बना है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की शामिल हैं।
- नाटो का एक महत्वपूर्ण पहलू वाशिंगटन संधि का अनुच्छेद 5 है, जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।
- भारत जैसे गैर-सदस्य देशों के साथ नाटो का जुड़ाव बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल होने और अपनी पारंपरिक सीमाओं से परे सहयोग को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को दर्शाता है।
- सदस्य देश संप्रभु राज्य हैं जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति से सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं।

इसका मुख्यालय बेलजियम के ब्रसेल्स में स्थित है।

Face to Face Centres





12 July, 2024

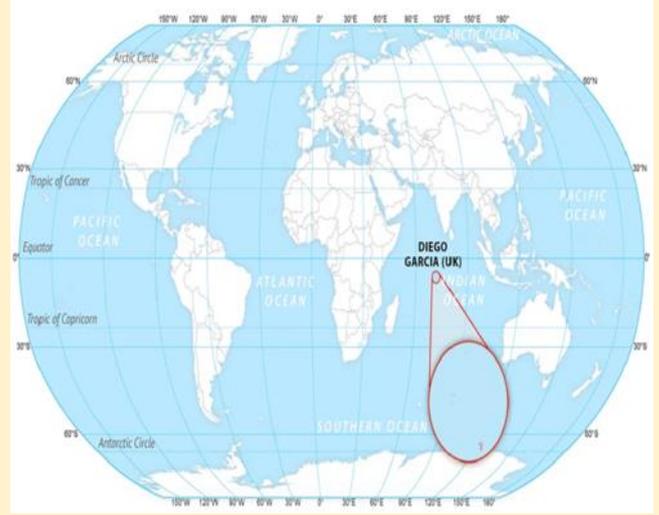
सुर्खियों में स्थल

डिएगो गार्सिया

हाल ही में, अमेरिकी सरकार ने डिएगो गार्सिया पर कथित रूप से गैरकानूनी प्रवासी हिरासत के मामले के संबंध में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में एक ब्रिटिश अदालत की सुनवाई को रोक दिया।

डिएगो गार्सिया के बारे में:

- डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, भारत के दक्षिणी तट से लगभग 1,600 किलोमीटर (1,000 मील) दक्षिण में स्थित है।
- डिएगो गार्सिया की खोज 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने की थी और इसका नाम नाविक डिएगो गार्सिया डी मोगुएर के नाम पर रखा गया था।
- यह एक एटोल है, जो चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें एक लैगून है जो कोरल रीफ से घिरा हुआ है।
- यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) का हिस्सा है, जो एक ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है।
- यहां एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डे है, जो हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में संचालन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- इसे 1965 में मॉरीशस से अलग करके नव निर्मित ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया था।
- चागोस द्वीपसमूह पर एक क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, जिसमें मॉरीशस संप्रभुता का दावा करता है।
- सैन्य अड्डे के लिए रास्ता बनाने के लिए 1960 और 1970 के दशक में मूल चागोसियन लोगों के जबरन विस्थापन के बारे में भी विवाद है।



POINTS TO PONDER

- मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारणी जलाशय (सतपुड़ा बांध) से किस विदेशी प्रजाति ने आक्रामक खरपतवार साल्विनिया मोलेस्टा को सफलतापूर्वक समाप्त किया? – साइरटोबैगस साल्विनिया
- न्यूप्सेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में 100 किलोग्राम मैक्स टेक ऑफ वेट (एमटीओडब्ल्यू) मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का परीक्षण किया: – अनमिंग ला दर्रा (पूर्वी लद्दाख में स्थित)
- 10 जुलाई 2024 को मॉरीशस द्वारा आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डीएनएसए) स्तर की बैठक के दौरान, किस देश का सीएससी के पांचवें सदस्य राज्य के रूप में स्वागत किया गया? – बांग्लादेश
- कौन सा संगठन महाराष्ट्र के कराड में भारत के वैज्ञानिक गहन ट्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है? – बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी
- पापुआ न्यू गिनी को भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) किस साझेदारी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती करती है? – भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)

Face to Face Centres

